Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना
Pradhan Mantri Awas Yojana

गरीबों की खुशहाली के 10 वर्ष

Research Team

Abhay Singh
Research Associate
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Manujam Pandey
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Design

Ajit Kumar Singh
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

विषय सूची

1	भूमिका	3
2	गरीबों का मसीहा	5
3	गरीब कल्याण के 10 वर्ष **- डॉ बाला लखेंद्र**	11
4	अमृतकाल में गरीब कल्याण से विकसित बनेगा भारत **- अजय धवले**	14

भूमिका

भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता प्रदान करता है और उनमें से प्रत्येक के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देता है. इसके बावजूद आजादी के कई दशकों के बाद भी कई भारतीयों में सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी रही. इसे बदलना था और तेजी से बदलना था. 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार विकास का एक मॉडल स्थापित कर चुकी है.

विकास का यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि कोई भी पीछे न रहे. ऐसा विकास जो न केवल कुछ चुनिन्दा लोगों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवा, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देता है.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पिछले दस वर्षों में प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है जिसे मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है.

मुद्रा योजना के तहत 46 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए जिनमें आधे से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को दिया गया है. यह न केवल व्यक्तियों के सशक्तिकरण की शुरुआत कर रहा है बल्कि पारंपरिक रूप से उपेक्षित समुदायों को सशक्त बनाने का भी कार्य कर रहा है.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के गरीब कल्याण संबंधी प्रावधान और कार्यक्रमों को वैश्विक संस्थानों से मान्यता मिली है. आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफ़ोर्ड जैसी संस्थाओं ने भारत को अपने सभी दस बहुआयामी गरीबी संकेतकों में कमी लाने का श्रेय दिया है.

गरीबों और वंचितों की सेवा करना प्रधानमंत्री मोदी का वादा रहा है. एक ऐसा वादा जो अन्त्योदय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जिसका अर्थ है कि विकास का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि यह समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचता.

इस ई-बुकलेट में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और उपलब्धियों का संकलन किया गया है.

डॉ अनिर्बान गांगुली

चेयरमैन - डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन,

नई दिल्ली

गरीबों का मसीहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ऐसे ही गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाता है। वह गरीबों के उत्थान के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। बीते 10 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबों के कल्याण के लिए नीतियां और योजनाएं बनीं और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ लागू भी किया गया। इतना ही नहीं योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पैनी नजर भी होती है और वे निरंतर लाभार्थियों से सीधे संवाद कर योजनाओं पर उनका फीडबैक भी लेते हैं। प्रधानमंत्री की सजगता की वजह से जहां योजनाओं का पूरा लाभ गरीबों को मिल रहा है, वहीं गरीबों की संख्या में तेजी से कमी भी आ रही है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पिछले एक दशक के दौरान भारत का आर्थिक सफर उल्लेखनीय प्रगति से भरा रहा है। विकास की रफ़्तार तेज कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक के सफ़र से पता चलता है कि देश उत्साह और आत्मविश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान गरीबों के जीवन एवं आजीविका में सुधार के लिए समर्पित और निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारत बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को 2030 से पहले हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। समाज के वंचितों और हाशिए के लोगों के उत्थान की दिशा में मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया और इस बदलाव को कई प्रभावशाली योजनाओं के जरिये स्पष्ट

तौर पर देखा जा सकता है। इसकी बदौलत देश भर में समावेशी विकास कर 2047 तक विकसित भारत की एक ठोस बुनियाद रखी गई है।

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना** के तहत हर महीने 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त अन्न मिल रहा है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी)** के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए।
- **सौभाग्य योजना** के तहत 2.8 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई गई।
- सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा **कार्यक्रम आयुष्मान भारत - पीएम जन आरोग्य योजना** के तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये के बीमा कवर के साथ 55 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित किया गया है।
- **जल जीवन मिशन** के तहत 14.50 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया।
- **पीएम उज्ज्वला योजना** के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन की बदौलत 10 करोड़ से अधिक महिलाएं को मिला स्वस्थ जीवन।
- **स्वच्छ भारत मिशन** के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए।
- लगभग 52 करोड़ जन धन खातों ने वित्तीय समावेशन के द्वार खोले।
- **पीएम स्वनिधि योजना** के तहत 62 लाख से अधिक शहरी रेहड़ी-पटरी वालों को करीब 11,000 करोड़ रुपये का बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया गया।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना** - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत अब तक 10.04 करोड़ महिलाओं को 90.76 लाख स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया।

सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण

पिछले एक दशक के दौरान सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस बदलाव ने देश भर में मानव विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसे कार्यक्रमों ने लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करते हुए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

की है। इसी प्रकार पीएम उज्ज्वला योजना मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करती है, आयुष्मान भारत योजना सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर तक नल के जरिये पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, पीएम-आवास योजना के जरिए किफायती मकानों की गारंटी मिली। इन सभी योजनाओं ने बदलाव को रफ्तार दी।

- **खाद्य सुरक्षा:** पीएमजीकेएवाई एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को हर महीने मुफ्त अन्न उपलब्ध कराया जाता है।
- **स्वच्छ भारत मिशन:** स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय और 2.33 लाख सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण हुआ है। इस व्यापक स्वच्छता कवरेज ने न केवल स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि महिलाओं को सम्मान प्रदान करते हुए उन्हें सशक्त भी बनाया।
- **जल जीवन मिशन:** जल जीवन मिशन के तहत 3.23 करोड़ से बढ़कर अब तक 14.50 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। अब देश में करीब 75 प्रतिशत भारतीय परिवारों को नल जल की सुविधा और स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है।
- **आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना** (ग्रामीण एवं शहरी) ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए क्रमशः 3.31 करोड़ और 81.03 लाख मकानों का निर्माण करते हुए किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा किया है।
- **स्वच्छ रसोई ईंधन:** पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.3 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इससे गरीब परिवार भी स्वच्छ रसोई ईंधन का उपयोग कर पा रहा है। महिलाओं को स्वस्थ जीवन सुनिश्चित हुआ है।
- **बिजली:** विकास के लिए बिजली की उपलब्धता आवश्यक है। सौभाग्य योजना के तहत बिना बिजली वाले 2.81 करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली उपलब्ध कराई गई है।

किफायती स्वास्थ्य

भारत में स्वास्थ्य सेवा, खासकर वंचितों के लिए इसकी पहुंच और सामर्थ्य लंबे समय से गंभीर चुनौतियां रही हैं। लेकिन, भारत ने अपने नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को किफायती एवं सुलभ बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है, जो अनवरत जारी है। इस यात्रा को स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे की मजबूती, वित्तीय बोझ में कमी और घर के आसपास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता पर केंद्रित विभिन्न प्रभावशाली

Ayushman Bharat Yojana

कार्यक्रमों से गति मिल रही है।

- **आयुष्मान भारत योजना:** यह योजना 55 करोड़ से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रही है। अब तक 33 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 81,979 करोड़ रुपये खर्च के साथ 6.50 करोड़ से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान की गई है। यह योजना लोगों को देश भर के अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवा भी प्रदान कर रही है।
- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर:** 1.69 लाख से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में एबी-एचडब्ल्यूसी) में अपग्रेड किया गया है। अब तक 22 करोड़ से अधिक मरीजों ने इन केंद्रों के जरिये ई-संजीवनी ओपीडी सेवाओं का लाभ लिया है। ई-संजीवनी ओपीडी के तहत टेलीमेडिसिन परामर्श की सुविधा प्रदान की गई है।
- **दवाओं को किफायती बनाना:** भारत सरकार ने अब तक देश भर में 11,096 जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। इन दवा दुकानों पर आवश्यक दवाएं बाजार मूल्य के मुकाबले 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती दरों पर उपलब्ध होती हैं। इससे कम आय वाले परिवारों के खर्च में कमी आई है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) ने देश के आम नागरिकों के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है।
- **घातक बीमारियों से मुकाबला:** राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जैसी पहल के प्रभावशाली परिणाम मिले हैं। वर्ष 2015 से 2022 के बीच टीबी के मामलों में 16 प्रतिशत की कमी आई है और मृत्यु दर में 18 प्रतिशत की कमी आई है।
- **मातृ स्वास्थ्य:** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये सीधे तौर पर नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 3.32 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,888 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय समावेशन

पिछले एक दशक के दौरान देश में वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक कल्याण की दिशा में जबरदस्त बदलाव आया है। मोदी सरकार ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देकर आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के जरिये कहीं अधिक समावेशी एवं सुरक्षित समाज को बढ़ावा देकर लाखों लोगों और परिवारों को सशक्त बनाया है। पीएम जन धन योजना जैसे सरकारी कार्यक्रम ने वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचाकर वित्तीय खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम जीवन ज्योति योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना किफायती दरों पर जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा प्रदान कर रही है। अटल पेंशन योजना बचत को प्रोत्साहित करती है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना एवं पीएम किसान मानधन योजना असंगठित

श्रमिकों एवं किसानों के लिए पेंशन सुनिश्चित करती हैं।

- **सुगम जीवन एवं दुर्घटना बीमा:** कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जरूरतों को समझते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) बेहद किफायती दरों पर जीवन बीमा एवं दुर्घटना बीमा प्रदान करती हैं। अब तक 19.18 करोड़ लोगों को पीएमजेजेबीवाई के साथ और 42.45 करोड़ लोगों को पीएमएसबीवाई से सशक्त बनाया गया है। इससे कम आय वाले परिवारों के सदस्यों की मृत्यु होने या दिव्यांगता जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से उबरने में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच मिला है।
- **भविष्य को सुरक्षित करना:** अटल पेंशन योजना खास तौर पर स्वरोजगार एवं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बीच सेवानिवृत्ति के लिए नियमित बचत को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत अब तक 6.20 करोड़ सबस्क्राइबर्स जुड़ चुके हैं। इससे बुढ़ापे के लिए वित्तीय स्वतंत्रता एवं सम्मान सुनिश्चित होता है।
- **असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन:** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हुए पीएम श्रम योगी मानधन योजना 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3,000 रुपये का पेंशन सुनिश्चित करती है। योजना के तहत 49.7 लाख पंजीकरण हो चुके हैं और यह उन लाखों श्रमिकों के लिए बेहद आवश्यक सामाजिक सुरक्षा एवं संतुष्टि प्रदान करता है जो अक्सर पारंपरिक पेंशन योजनाओं से बाहर होते हैं।

रोजगार एवं कौशल विकास

बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने रोजगार परिदृश्य में जबरदस्त बदलाव देखा है। यह विकास आर्थिक सुधारों, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास पर जोर सहित मोदी सरकार के विभिन्न योजनाओं का नतीजा है। कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न ढांचागत सुधार मौजूदा दशक में उत्पादक रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। 'मेक इन इंडिया' विदेशी निवेश को आकर्षित करते हुए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है जिससे नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। कारोबारी सुगमता जैसे सुधारों के जरिये नियमों को उपयुक्त और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से उद्यमशीलता एवं छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिला है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दिया है। जिसने सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स एवं अन्य डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। भारत का आर्थिक उत्थान महज वृहद आर्थिक आंकड़ों पर ही नहीं, बल्कि यह अपने नागरिकों को उपयुक्त कौशल एवं रोजगार क्षमता के साथ सशक्त बनाने पर भी केंद्रित है।

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

- **पीएम कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में अब तक 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। पीएम कौशल विकास योजना उद्योग के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण

एवं प्रमाणन के जरिये लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर उनकी आजीविका में सुधार लाने का काम कर रही है।

- **स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म:** यह प्लेटफॉर्म भारत में सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।
- **राष्ट्रीय अप्रैंटिसशिप संवर्धन योजना (एनएपीएस):** योजना के तहत 26.9 लाख अप्रैंटिस के साथ युवाओं को बेहद आवश्यक व्यावहारिक अनुभव और उद्योग में अनुभव हासिल करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
- **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना:** आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों) के जरिये इस योजना के तहत 2014-22 के बीच 1.1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

उद्यमशीलता

पिछले एक दशक के दौरान भारत में उद्यमशीलता की भावना में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। यह भावना समाज के विभिन्न वर्गों को लक्षित करने वाली विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से प्रेरित है। इन कार्यक्रमों ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि हाशिए पर मौजूद समुदाय के लोगों को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकालने और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण को भी बढ़ावा दिया है।

- **पीएम मुद्रा योजना:** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का उद्देश्य नई या मौजूदा सूक्ष्म इकाइयों/उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के संस्थागत ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत 26 जनवरी, 2024 तक कुल 46.15 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27.38 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- **पीएम स्वनिधि:** अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वेंडर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 86.95 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 62.36 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 11,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इस प्रकार यह उन्हें अपने कारोबार को औपचारिक बनाने और अपनी आजीविका को बेहतर करने के लिए सशक्त बनाती है।
- **डीएवाई-एनआरएलएम:** अब तक 10.04 करोड़ महिलाओं को 90.76 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। डीएवाई-एनआरएलएम महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन, नेतृत्व कौशल और सामूहिक कार्य को बढ़ावा देती है। यह उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने, आय अर्जित करने और सामुदायिक विकास में योगदान के लिए सशक्त बनाती है।

गरीब कल्याण के 10 वर्ष

- डॉ बाला लखेंद्र

पिछले एक दशक के दौरान भारत का आर्थिक सफर एक दमदार एवं उल्लेखनीय प्रगति से भरा रहा है। विकास की रफ़्तार तेज करने, वैश्विक चुनौतियों से निपटने और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने से साफ तौर पर पता चलता है कि देश उत्साह, नवाचार एवं महत्वाकांक्षा की भावना से ओतप्रोत है। मगर इस विकास को वास्तव में टिकाऊ बनाने, समावेशी बनाने और समृद्धि एवं हाशिए के बीच की खाई को ख़त्म करने की जरूरत है।

बाजार की ताकतें अक्सर वंचितों के सामने आने वाली चुनौतियों का अपने दम पर समाधान करने में विफल रहती हैं। व्यवस्था संबंधी बाधाएं, संसाधनों तक सीमित पहुंच और ऐतिहासिक असमानताएं व्यक्तियों एवं समुदायों को गरीबी व उपेक्षा के चक्र में फंसा सकती हैं। इससे निपटने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन की गई

नीतियों और योजनाओं की परिवर्तनकारी शक्ति की जरूरत दिखती है। यह खाई को पाटने के लिए एक पुल के रूप में कार्य करती है, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है और हर किसी को न केवल जीवित रहने, बल्कि आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाती है।

व्यवस्था संबंधी इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने पिछले दस वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लागू किया है। इन कार्यक्रमों ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लक्षित करते हुए उन्हें गरीबी के चक्र से मुक्त होने और देश के विकास में सक्रिय योगदान करने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान गरीबों के जीवन एवं आजीविका में सुधार के लिए समर्पित और निरंतर प्रयास किए गए हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर महीने 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त अन्न मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं। सौभाग्य योजना के तहत 2.8 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई गई है। सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत - पीएम जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये के बीमा कवर के साथ 55 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 14.50 करोड़ ग्रामीण परिवारों को (14 मार्च, 2024 तक) नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन की बदौलत 10 करोड़ से अधिक महिलाएं अब आसानी से सांस ले रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे लाखों लोगों के जीवन में गरिमा एवं स्वच्छता आई है। लगभग 52 करोड़ जन धन खातों ने वित्तीय समावेशन के द्वार खोले और लोगों को औपचारिक प्रणाली में शामिल किया है।

पीएम स्वनिधि योजना (14 मार्च, 2024 तक) के तहत 62 लाख से अधिक शहरी रेहड़ी-पटरी वालों को करीब 11,000 करोड़ रुपये का बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत 13 मार्च, 2024 तक 10.04 करोड़ महिलाओं को 90.76 लाख स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का प्रमाण है। इसके अलावा लाखों लोग स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और सस्ते आवास कार्यक्रमों तक पहुंच से लाभान्वित हुए हैं।

परिणामस्वरूप, भारत बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को 2030 से पहले हासिल कर सकता है। सबसे कमजोर एवं वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की

प्रतिबद्धता एवं समर्पण ने इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालांकि समावेशी विकास की दिशा में सफर अभी जारी है। मगर इसमें मौजूद जटिलताओं को पहचानते हुए सरकार अपने प्रयासों का लगातार मूल्यांकन एवं समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समावेशी विकास लक्षित लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी तौर पर पहुंच सके।

भारत में स्वास्थ्य सेवा, खासकर वंचितों के लिए पहुंच और सामर्थ्य लंबे समय से गंभीर चुनौतियां रही हैं। मगर भारत ने अपने नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को किफायती एवं सुलभ बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। इस यात्रा को स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे की मजबूती, वित्तीय बोझ में कमी और घर के आसपास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ सेवा की उपलब्धता पर केंद्रित विभिन्न प्रभावशाली कार्यक्रमों से गति मिल रही है।

पिछले एक दशक के दौरान सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है, जो अल्पकालिक उपायों के बजाय दीर्घकालिक सशक्तिकरण एवं दूरदर्शी टिकाऊ प्रभाव पर केंद्रित हो गया है। इस बदलाव के कारण अधिक क्षमतावान कल्याणकारी व्यवस्था तैयार हुई है और इसने देश भर में मानव विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसे कार्यक्रम ने लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करते हुए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसी प्रकार पीएम उज्ज्वला योजना मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करती है, आयुष्मान भारत योजना सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर तक नल के जरिये पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और पीएम-आवास योजना किफायती मकानों की गारंटी देती है। इन सब योजनाओं से बदलाव को रफ्तार मिली है। ये कार्यक्रम लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के बजाय भविष्य के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं और लोगों को अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के लिए सही उपकरणों से लैस करते हैं।

(लेखक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं)

अमृतकाल में गरीब कल्याण से विकसित बनेगा भारत

- अजय धवले

आज हम अमृतकाल में भारत के अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति की बात कर रहे है। आज हमारा भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनकर दूसरे जरूरतमंद राष्ट्रों की आवाज भी बन रहा है और उनकी मदद भी कर रहा है। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों के साथ 140 करोड़ देशवासियो को 2047 तक विकसित भारत बनाने हेतु प्रेरित किया है। कुछ प्रमुख वैश्विक एजेंसियों के अनुमान अनुसार अगले 5 से 6 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

भारतीय राजनीति पर मोदी सरकार का प्रभाव बहुआयामी एवं महत्वपूर्ण है। मोदी जी के सरकार ने जनहितैषी

नीति निर्माण और उनके सफल कार्यान्वयन का एक नया युग शुरू किया है। हालाँकि, सरकार के शुरुवाती दौर में पूर्ववर्ती सरकारों के समय से चली आ रही आर्थिक एवं सामजिक उत्थान कई नीतियों को समयानुकल बनाने के लिए एवं धारा के विपरत जाकर देश की 140 करोड़ जनता के कल्याण को केंद्रबिंदु बनाने हेतु सरकार को आलोचनाओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, जो भारत जैसे विविध और तेजी से बदलते देश पर शासन करने की जटिलता को दर्शाता है। हम ने यह भी देखा है की समग्र विकास, कल्याण और आर्थिक सुधार पर सरकार के जोर ने राजनीतिक चर्चा और चुनाव परिणामों को आकार दिया है। एक ओर सरकार की नीतियों ने स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच में सुधार करने में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है वही सामाजिक-आर्थिक नीतियों ने भारत की विकास यात्रा में योगदान दिया है ।

पिछले 10 वर्षों लगभग 4 करोड़ पीएम आवास घर, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन, पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में लगभग 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रतिमाह दिया। हर घर जल के तहत लगभग 13 करोड़ नल से जल कनेक्शन, सौभाग्य के माध्यम से अंतिम गांव तक बिजली और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का व्यापक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। मुद्रा, स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के साथ मिलकर इन योजनाओं ने मध्यम वर्ग को अपने अस्तित्व से अवगत कराया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं तथा उसी उद्देश्य से गरीब कल्याण के लिए नीतियां और योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाता है। योजनाओं

के क्रियान्वयन पर प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नजर होती है। वे समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से सीधे संवाद कर फीडबैक लेते रहते हैं। उनकी सजगता की वजह से जहां योजनाओं का पूरा लाभ गरीबों को मिल रहा है, वहीं गरीबों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है।

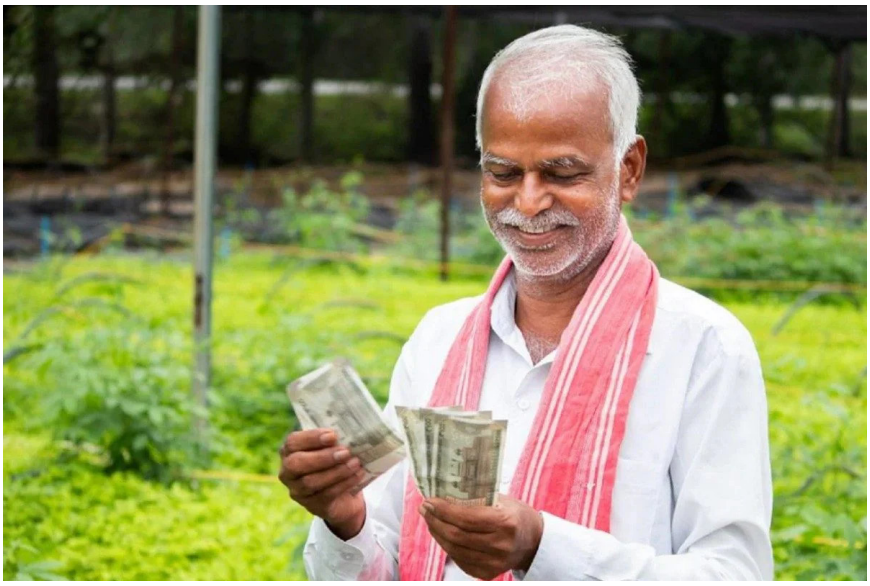

हाल ही में नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), ऑक्सफोर्ड नीति और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) के इनपुट के आधार पर एक शोधपत्र जारी किया है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद द्वारा तैयार इस शोधपत्र में 2013-2014 से 2022-23 के बीच गरीबों की संख्या में तेजी से आई कमी के आंकड़े दिए गए हैं। शोधपत्र के अनुसार पिछले नौ वर्षों में देश के 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वर्ष 2013-2014 में भारत की 29.17 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जबकि वर्तमान समय में ये आंकड़ा घटकर 11.28 प्रतिशत रह गया है।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नीति आयोग की इस रिपोर्ट की प्रसंशा कर कहा कि यह रिपोर्ट काफी उत्साहजनक है। यह समावेशी विकास को बल देने और अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और उनकी सरकार समृद्ध भविष्य के लिए समग्र विकास की दिशा में काम करना जारी रखेगी।

वास्तव में यदि हम आंकड़ों की बात करे तो 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए यानी प्रत्येक वर्ष 2.75 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। शोधपत्र के अनुसार गरीबी में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में 5.94 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ गरीबों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्यप्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (Crisil) ने भी भारत की नीतियों सराहा है। क्रिसिल ने अपनी 'इंडिया आउटलुक' रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू संरचनात्मक सुधारों और चक्रीय स्थितियों से समर्थन मिलेगा और यह वर्ष 2031 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपनी वृद्धि संभावनाओं को बरकरार रखने के साथ उसमें सुधार भी कर सकती है। साथ ही क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है और भारत की अर्थव्यवस्था भी दोगुनी होकर 7 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी यह भी कहा है। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है की 2030-31 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय भी अपर मिडिल इनकम ग्रुप तक पहुंच जाएगी जिससे हमारा भारत अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा।

हमारा भारत एक कल्याणकारी देश है। सरकार की प्राथमिकता सामान्य नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना यह सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य के साथ मोदी जी सरकार ने एक तरफ नई योजनाएं बनाई, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सुनिश्चित किया कि योजना का लाभ हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचे। विगत दस वर्षो में सरकार ने सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं बल्कि देश के भविष्य पर भी निवेश किया। है। मोदी सरकार के प्रतीक प्रत्येक बजट में चार मुख्य कारकों पर ही केंद्रित रखा जिसमे पूंजीगत व्यय के रूप में रिकॉर्ड लाभकारी व्यय, कल्याणकारी योजनाओं पर अभूतपूर्व निवेश, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन का समावेश है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते है की सरकार अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में "एक पैसा बचाना, एक पैसा कमाना है" के मंत्र को पर कार्य करती है, उदाहरण के तौर पर अनेक परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का का लक्ष्य रखा गया। क्योकि विलम्ब के कारण परियोजना की लागत बढ़ती है।

प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए देश के पैसे बचाने के प्राथमिकता दी है इसी वजह से सरकार ने 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों से छुटकारा पाया है जो केवल कागजों पर उपस्थित थे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए धन का दुरूपयोग रोका गया, जिसकी वजह से 3.25 लाख करोड़ रुपये की राशि को गलत हाथों में जाने बची। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात पर बल देते है की हम वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली अनेकों पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हैं। इसलिए नीतियों और निर्णयों में वित्तीय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

हाल ही में एक सार्वजनकि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सात दशक पहले से हमारे यहां गरीबी हटाओ के नारे दिन–रात दिए जाते रहे हैं। लेकिन वे किसी तरह का प्रभाव डालने में विफल रहे और वातानुकूलित कमरों से सुझाव देने वाले लोग करोड़पति बन गए, जबकि गरीब, गरीब ही बने रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद चौतरफा काम शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। उन्होंने इसका श्रेय अपनी सरकार की नीतियों को दिया। श्री मोदी ने कहा, "मैं गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा हूं इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश की गरीबी कम करेंगे, अपने देश को विकसित बनाएंगे।

(लेखक कॉर्पोरेट लॉयर हैं, प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee

Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

Phone: 011-69047014

@spmrfoundation